सिविल विविध

माननीय न्यायमूर्ति पी. डी. शर्मा के समक्ष

मनमोहन कौर, - याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य, - उत्तरदाता

1967 की सिविल रिट संख्या 2273

18 मार्च, 1968।

पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर (1964) - खंड 2- विनियमन 2 (ई) (आई) - शिक्षक/व्याख्याता शब्द में क्या मानद शिक्षक/व्याख्याता शामिल है।

यह माना गया कि जहां भी विश्वविद्यालय मानद क्षमता में काम करने वाले शिक्षकों और व्याख्यानों को बाहर करना चाहता है, वे प्रावधान करते हैं कि जो शिक्षक पूरे समय के सदस्यों के अनुसार काम कर रहे थे, शिक्षण कर्मचारी निजी उम्मीदवारों के रूप में कुछ परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर (1964) खंड II के विनियमन 2 (ई) (i) के वाक्यांश विज्ञान से, यह किसी भी कारण से नहीं कहा जा सकता है कि "शिक्षक / व्याख्यान" शब्द में मानद क्षमता में काम करने वाले शिक्षक / व्याख्यान शामिल नहीं थे। यह शब्द केवल प्रति शिक्षक / व्याख्याता से संबंधित नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका। प्रार्थना करता हूं कि 10 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या बीटी/64 - बी/11 पर सवाल उठाते हुए एक आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से नागेंद्र, सिंह, वकील

एच.आर.सोढ़ी, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए

माननीय न्यायमूर्ति पी. डी. शर्मा- प्रतिवादी पंजाब विश्वविद्यालय ने 10 दिसंबर, 1964 की अपनी अधिसूचना संख्या बीटी/64-बी/1 द्वारा याचिकाकर्ता को सितंबर, 1964 के महीने में आयोजित बैचलर ऑफ टीचिंग परीक्षा में सफल घोषित किया था। इस अधिसूचना को बाद में 10 अगस्त, 1965 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के परिणाम को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में बाद की अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया है। उन्होंने जून, 1963 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने जुलाई, 1963 से श्री मातृ गंगा गर्ल्स हाई स्कूल, बाबा बकाला, जिला अमृतसर में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और सितंबर, 1964 के महीने की शुरुआत तक ऐसा करना जारी रखा। उन्होंने सितंबर, 1964 के महीने में रोल नंबर 12 के तहत एक निजी उम्मीदवार के रूप में अपनी बैचलर ऑफ टीचिंग परीक्षा दी क्योंकि उन्होंने शिक्षा संकाय के बैचलर ऑफ टीचिंग की डिग्री के विनियमन संख्या 2 (ई) (आई) के तहत परीक्षा शुरू होने की तारीख से 12 महीने तक एक शिक्षक के रूप में काम किया था। उन्हें शुरुआत में सफल घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उनके परिणाम को लागू अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर यह अवैध, अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक, शून्य और अधिकार क्षेत्र से परे था:-

1. याचिकाकर्ता को न तो कोई नोटिस दिया गया था और न ही उसके बीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया था;

X X X X X X

6. यह कि शिक्षा संकाय के बैचलर ऑफ टीचिंग की डिग्री के विनियमन 2 (ई) (आई) के अनुसार, याचिकाकर्ता एक निजी उम्मीदवार के रूप में बीटी परीक्षा में बैठने के लिए काफी योग्य था;
7. प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध 'डी' में दिया गया कारण कि मानद शिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता एक निजी उम्मीदवार के रूप में बीटी

परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं था, संबंधित विनियमों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

याचिका में उल्लिखित अन्य आधारों पर जोर नहीं दिया गया।

2. पंजाब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अपने लिखित बयान में दलील दी कि रिट याचिका में काफी देरी हुई है और याचिकाकर्ता एक मानद शिक्षक के रूप में काम करता है और इस तरह एक निजी उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होने के लिए वैधानिक विनियमों के तहत योग्य नहीं है। उसने प्रवेश फॉर्म में इस तथ्य को दबा दिया और इसलिए एक गलती के तहत परीक्षा देने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता के परिणाम की घोषणा के बाद, अमृतसर के कैलाश नंदा द्वारा हस्ताक्षरित कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई कि याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी से अपनी पात्रता प्राप्त की क्योंकि वह कभी भी किसी स्कूल में शिक्षक नहीं रही थी। इस शिकायत को हेड मिस्ट्रेस, एसएमजी गर्ल्स हाई स्कूल, बाबा बकाला को भेजा गया था, जिन्होंने तथ्यों की रिपोर्ट करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रवेश फॉर्म, अनुलग्नक आर-1 को सत्यापित किया था। हेड मिस्ट्रेस ने अपने पत्र के अनुलग्नक आर-2 की प्रति के माध्यम से सूचित किया कि याचिकाकर्ता को 9 मई, 1963 को स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा मानद शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 19 सितंबर, 1964 तक इसी रूप में कार्य करती रही। रजिस्ट्रार ने कहा कि विनियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता एक निजी उम्मीदवार के रूप में बीटी परीक्षा नहीं दे सकता था और जब सही तथ्य ज्ञात थे, तो पहले से घोषित परिणाम रद्द कर दिया गया था।

3. स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1963 में पंजाब विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्होंने जुलाई, 1963 से सितंबर, 1964 की शुरुआत तक बाबा बकाला के एसएमजी गर्ल्स हाई स्कूल में मानद शिक्षक के रूप में काम किया। प्रवेश फॉर्म, अनुलग्नक आर-1 से यह भी पेटेंट है कि याचिकाकर्ता ने इसमें मानद क्षमता में एक शिक्षक के रूप में काम करने के बारे में उल्लेख नहीं किया था। उन्हें सितंबर, 1964 में आयोजित बैचलर ऑफ टीचिंग की परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी, और उसी वर्ष सफल घोषित किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय को पता चला कि याचिकाकर्ता ने मानद क्षमता में शिक्षक के रूप में काम किया था, पहले से घोषित

परिणाम को रद्द कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि कैलेंडर खंड 11-1964-65 के पृष्ठ 384 पर बैचलर ऑफ टीचिंग की डिग्री का विनियमन 2 (ई) याचिकाकर्ता के मामले पर लागू होता है जो निम्नानुसार है: –

"लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय की कोई भी महिला स्नातक जिसने 1947 में डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या इस विश्वविद्यालय से पहले, या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (सिंडिकेट की मंजूरी के अधीन) जो -

1. पंजाब और हिमाचल प्रदेश के भीतर, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में या सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित स्कूल में या इस विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में, आवेदन की तारीख से पहले किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के लिए परीक्षा शुरू होने की तारीख से बारह महीने के लिए शिक्षक / व्याख्याता के रूप में काम कर रहा है और निजी उम्मीदवारों के लिए नियमों के तहत भर्ती किया गया है;

नहीं तो

2. आवेदन की तारीख से पहले किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के लिए परीक्षा शुरू होने की तारीख से बारह महीने तक पंजाब या हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के स्कूलों के सहायक या जिला निरीक्षक के रूप में काम कर रहा है और निजी उम्मीदवारों के लिए नियमों के तहत भर्ती है।

कैलेंडर में पुन: प्रस्तुत किए गए विनियमन में पंक्ति तीन में 'पहले' और 'के' शब्दों के बीच 'या' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जो एक मुद्रण गलती है, जैसा कि पंजाब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को लिखे गए पत्र से स्पष्ट है। दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पंजाब विश्वविद्यालय के पृष्ठ 165 पर 'निजी उम्मीदवार' शीर्षक के तहत अध्याय VII में विनियम 2 (बी) कैलेंडर खंड I, 1964-65 में याचिकाकर्ता के मामले को शामिल किया गया था। यह विनियम निम्नलिखित शर्तों में है -

"नियम । और 9 के अधीन, सीनेट, सिंडिकेट की सिफारिश पर, निम्नलिखित वर्गों के उम्मीदवारों को भाषा और कला संकाय में

विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेश के लिए अनुमति दे सकता है, बिना उनके निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा किए बिना।

विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में, या विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में,यदि वे अन्यथा परीक्षा के लिए नियमों के तहत उपस्थित होने के लिए पात्र हैं।

* * * *■ *

(ख) ऐसे शिक्षक जो नीचे विनिर्दिष्ट संस्थाओं में पूर्णकालिक शिक्षण स्टाफ के सशुल्क सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे हैं और आवेदन की तारीख को या तो कुल मिलाकर दो वर्ष की अवधि के लिए या लगातार बारह महीने की अवधि के लिए ऐसी सेवा में रहे हैं और संबंधित संस्था के प्रमुख द्वारा अनुशंसित हैं: ''

मेरी राय में उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए विनियमन का मामले से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि यह निजी उम्मीदवारों के पेश होने से संबंधित है? कला और ओरिएंटल संकायों में डिग्री परीक्षाओं के लिए। यह सामान्य आधार है कि शिक्षा इन संकायों में से किसी के अंतर्गत नहीं आती है और एक स्वतंत्र, संकाय है। प्रतिवादियों के वकील ने आगे आग्रह किया कि वर्ष 1937-38 के लिए पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के पृष्ठ 129 पर अध्याय 11 में निजी उम्मीदवारों से संबंधित विनियमन, जिसे पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2 (आई) ए द्वारा बचाया गया था, याचिकाकर्ता के मामले को नियंत्रित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब सरकार के एक विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत एक शैक्षणिक संस्थान का केवल पूर्णकालिक शिक्षण कर्मचारी पंजाब विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा में एक निजी उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होने के लिए पात्र था, लेकिन मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए विनियमन की घोषणा के साथ 1937-38 का यह विनियमन निरस्त हो गया था।

3. केवल एक बिंदु जो निर्धारित किया जाना बाकी है, वह यह है कि "पंजाब और हिमाचल प्रदेश के भीतर एक शिक्षक / व्याख्याता के रूप में काम कर रहा है" शब्द में मानद शिक्षक / व्याख्याता शामिल हैं। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित दो विनियमों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि जहां भी विश्वविद्यालय मानद क्षमता में काम करने वाले शिक्षकों और व्याख्याताओं को बाहर करना चाहता था, उन्होंने प्रावधान किया कि पूर्णकालिक शिक्षण

कर्मचारियों के भुगतान किए गए सदस्यों के रूप में काम करने वाले शिक्षक निजी उम्मीदवारों के रूप में कुछ परीक्षाओं में उपस्थित हो सकते हैं। चूंकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित विनियमन के वाक्यांश विज्ञान और विपरीत पक्ष द्वारा भरोसा किए गए अलग-अलग हैं, इसलिए यह किसी भी कारण के साथ नहीं कहा जा सकता है कि "शिक्षक / व्याख्याता" शब्द में मानद क्षमता में काम करने वाले शिक्षक / व्याख्याता शामिल नहीं थे। इस प्रकार, विश्वविद्यालय को कक्षा के भीतर विनियमन की सरल भाषा की व्याख्या करने में उचित नहीं था, जिसका अर्थ यह था कि यह केवल भुगतान किए गए शिक्षक / व्याख्याता से संबंधित था। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को सितंबर, 1964 में उसके द्वारा ली गई बीटी परीक्षा के परिणाम को रद्द करने से पहले अपना मामला बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। यह प्राकृतिक न्याय के नियमों के भी खिलाफ था। इसके लिए और उपरोक्त लागू अधिसूचना को कानून में बुरा कहा जा सकता है।

4. रिट को जुर्माने के साथ अनुमति दी जाती है और आक्षेपित अधिसूचना अनुलग्नक 'सी' को रद्द किया जाता है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का परिणाम जो जल्दी घोषित किया गया था, रद्द कर दिया गया था।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशिमा गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरूग्राम, हरियाणा